जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 240 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 26 मार्च, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को नवरात्र पर्व की शुभकामना एवं बधाई दी तथा राजस्थान के शिल्पकार द्वारा चंदन की लकड़ी से निर्मित मां दुर्गा की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी से विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं और नीतियों के सफल क्रियान्वयन से आमजन लाभांवित हो रहे हैं। वहीं, राजस्थान विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां को छू रहा है।

## '24, अकबर रोड से कई यादें जुड़ी हैं'

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मार्च। कांग्रेस के मुख्यालय 24, अकबर रोड (पार्टी मुख्यालय) और 5 रायसीना रोड (युवा कांग्रेस कार्यालय) को खाली करने के लिए एस्टेट निदेशालय द्वारा दिए गए नोटिस पर पार्टी नेताओं का गुस्सा और नैतिकता का दावा कुछ हद तक गलत लगता है, हालांकि यह कहा जा सकता है कि ये नोटिस "बदले की राजनीति"

- **केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कांग्रेस को पूर्व मुख्यालय, 24 अकबर रोड को खाली करने के नोटिस पर वरिष्ठ पार्टी नेता बेहद भावुक हो रहे हैं, उनका कहना है, यहाँ से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हाराव और मनमोहन सिंह की यादें जुड़ी हुई हैं।**

का प्रतीक हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अदालत में ले जाने का फैसला किया है, ताकि उसे जबरन बाहर न किया जा सके।

शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय की 2006 की नीति के तहत, राजनीतिक दलों को नए कार्यालय बनाने के लिए जमीन दी जाती

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# मुख्यमंत्री बनने की चाह ने कितना बदल दिया के.सी. वेणुगोपाल को

## वेणुगोपाल केरल में अब घर-घर जा रहे हैं और उन रूष्ट कांग्रेस उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हैं, जिन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला और जो बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की तैयारी में हैं

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मार्च। के. सी. वेणुगोपाल को पार्टी में एआईसीसी के संगठन महासचिव की तरह व्यवहार करने में छह साल लग गए, इस समय भी वे यह जिम्मेवारी तब निभा रहे है, जब इससे उनका खुद का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे केरल के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

केरल में विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर हैं और के. सी. वेणुगोपाल इन दिनों केरल में सक्रिय हैं, जहां उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। वे लगातार घर-घर जाकर उन कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला या जो बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

उनका उद्देश्य इस बारगी प्रत्याशियों को शांत करना है, ताकि केरल चुनावों में पार्टी को कोई नुकसान न हो।

अब सवाल उठ रहा है कि संगठन महासचिव के रूप में वेणुगोपाल ने यही काम महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार या अन्य राज्यों में क्यों नहीं किया, जहां कांग्रेस बुरी तरह विधानसभा चुनाव हार

- **वेणुगोपाल केरल में पार्टी खेमेबाजी व अंतर विरोध को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं की आपसी रंजिश व मनमुटाव को समझाइश से बीच बचाव करके निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।**
- **वेणुगोपाल के इन सभी प्रयत्नों का एक ही ध्येय है, आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।**
- **पर, अहम् सवाल यह उठ रहा है कि ए.आई.सी.सी. में संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने ये ही प्रयत्न महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली व बिहार में क्यों नहीं किए, जहाँ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ा।**
- **शायद इन राज्यों में भी कांग्रेस की इतनी भारी हार नहीं होती, अगर संगठन महासचिव इन राज्यों में भी अपनी "जॉब-प्रोफाइल" के अनुरूप सक्रियता दिखाते।**

गई।

क्या यह संगठन महासचिव के रूप में उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं था?

क्या इन राज्यों में गुटबाजी को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी?

क्या नाराज वरिष्ठ नेताओं को मनाना उनका कर्तव्य नहीं था?

या फिर यह सुनिश्चित करना, कि कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करे, उनकी भूमिका में शामिल नहीं था?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# 'अपनी हार को समझौते का जामा पहनाने की कोशिश न करें'

## ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के पन्द्रह सूत्री "शांति प्रस्ताव" की खिल्ली उड़ाई

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 मार्च। पश्चिम एशिया के युद्ध को समाप्त करने के लिए पंद्रह बिंदुओं की एक शांति योजना ईरान भेजी गई है, ताकि क्षेत्र में शत्रुता समाप्त हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान जल्द से जल्द शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है।

पाकिस्तान का कहना है कि उसने ट्रंप के पंद्रह बिंदुओं का एजेंडा ईरान तक पहुंचाया है, पर इज़रायल के अनुसार, ईरान द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के सभी प्रयासों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह केवल ईरान की शर्तों पर होगा, अमेरिका की शर्तों पर नहीं।

पाकिस्तान ने युद्धरत पक्षों के बीच वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश की है। तुर्की और मिस्र भी यह कह रहे हैं कि वे दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, ईरान ने कहा है कि जितनी अधिक बार यह गलत जानकारी दोहराई जाएगी कि ईरान शांति योजना के लिए विनती कर रहा है, उतना ही वह ऐसे प्रस्तावों के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाएगा।

- **ईरान ने यह भी कहा कि उसका अमेरिका से किसी भी तरह का सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ है, साथ ही ईरान ने पुरजोर तरीके से दावा किया कि वह अमेरिका से किसी भी तरह की "डील" पर बातचीत नहीं करेगा।**
- **गौरतलब बात यह भी है कि अमेरिका के सैन्य सामान का काफी कुछ भंडार खत्म हो गया है, ईरान के साथ युद्ध में, और अमेरिका के युद्ध मामलों के सचिव (मंत्री) पीट हेगसेथ हथियारों के खत्म होते भण्डार को पुनः भरने के लिए हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।**
- **पर, विडम्बना यह है कि आधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत "रेयर अर्थ मिनरल्स" की होती है, जिसके लिए अमेरिका को चीन के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं।**
- **ट्रंप को चीन पर यह निर्भरता कतई पसंद नहीं आ रही है और निर्भरता को खत्म करने के लिए निरंतर रास्ते ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने अमेरिका को "रेअर अर्थ मिनरल्स" सप्लाई के बारे में अपने रवैये को और सख्त कर दिया है।**

ट्रंप की शांति योजना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण खात्मा शामिल है, जिसमें यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने का वचन, सभी परमाणु प्रतिष्ठानों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और आईईए (इंटरनैशनल एनर्जी एजेन्सी) द्वारा निगरानी के लिए खोलना, तथा आत्मरक्षा के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर सभी मिसाइल उत्पादन और

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ईरान सिर्फ जेडी वैंस से बात करेगा

वॉशिंगटन, 25 मार्च। पश्चिम एशिया संकट के कूटनीतिक समाधान पर बातचीत चल रही है। इस बीच ईरान ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन को साफ संकेत दिया है कि वह अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ दोबारा बातचीत

- **अमेरिकन मीडिया संस्थान सीएनएन ने यह जानकारी दी और कहा इसकी वजह यह है कि वैंस शुरु से ही ईरान पर हमले के विरुद्ध है।**

नहीं करना चाहता। इसके बजाय, तेहरान की प्राथमिकता अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत करने की है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया संस्थान सीएनएन ने दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का मानना है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के साथ बातचीत विश्वास की कमी के कारण प्रभावी नहीं होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ही ईरानी सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे और वह बातचीत विफल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के समर्थक हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वेंस, ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे। यही वजह

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# मॉल की बेसमैंट पार्किंग पर क्या यूडी टैक्स वसूल सकता है नगर निगम?

## क्रिस्टल पाम के मालिकों ने नगर निगम द्वारा थमाए गए डिमांड नोटिस और यूडी टैक्स वसूली के नियम-कायदों को हाई कोर्ट में चुनौती दी

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 25 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर में 22 गोदाम सर्किल पर स्थित क्रिस्टल पाम मॉल के बेसमेंट में बनी पार्किंग का नगर निगम जयपुर द्वारा अरबरन डबलपमैंट (यूडी) टैक्स मांगे जाने को लेकर थमाए गए डिमांड नोटिस को मॉल के मालिक महिमा ग्रुप रियल एस्टेट प्रा. लि. ने चुनौती दी है। इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम के ज़ोन उपायुक्त को भी पक्षकार बनाया गया है।

इस मामले में कानूनी मुद्दा यह उठाया गया है कि मॉल की बेसमेंट पार्किंग, जो थर्ड पार्टी को संचालन के लिए दी जाती है, क्या वह कमर्शियल एक्टिविटी है और क्या उस पर यूडी टैक्स लागू किया जा सकता है?

मॉल मालिकों की ओर से नगर निगम के उन नियम-कायदों को चुनौती दी गई है, जिनके जरिए जयपुर में बकाया यूडी टैक्स वसूला जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता फलक माथुर पैरवी के लिए पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि नगर निगम के सिविल लाइंस ज़ोन ऑफिस ने क्रिस्टल पाम मॉल की बेसमेंट पार्किंग को व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए यूडी टैक्स चुकाने का नोटिस थमाया है। जिस नियम के अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा यूडी टैक्स वसूला जा रहा है, उस नियम में इमारतों की बेसमेंट पार्किंग को "कमर्शियल बिल्डिंग" का हिस्सा नहीं माना गया है। इस पार्किंग की जगह पर व्यवसायिक गतिविधि नहीं होती, यह सुविधा क्षेत्र है, जो मॉल में आने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाने के लिए है।

- **याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, मॉल्स में बेसमैंट पार्किंग आमजन की सुविधा के लिए होती है, यह कमर्शियल गतिविधि नहीं मानी जा सकती।**
- **वहीं, अदालत ने मॉल संचालकों को नगर निगम के कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है, अब इस प्रकरण में 27 मार्च को सुनवाई होगी।**

उन्होंने कहा कि इस सुविधा क्षेत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक नहीं होता, यह आमजन की पार्किंग सुविधा के लिए ही है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे नगर निगम के कर निर्धारक को इस बारे में अपनी आपत्ति भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस मामले में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल पैरवी के लिए पेश हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे ही मामले पर अदालत ने पूर्व में नगर निगम को आदेश दिए थे कि कर निर्धारण करने वाले ऑफिसर व्यापारियों की शिकायतों और आपत्तियों पर निष्पक्षता से उनका पक्ष सुनें। सभी तथ्यों को सुनने

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )